

**STRUGGLING TO MEET TARGETS...**

# Big Electoral Bond Buyer Megha Engg to Sell City Gas Biz

Possible valuation at ₹1,000-2,000 crore

Kalpana.Pathak@timesgroup.com

**Mumbai:** Hyderabad-based Megha Engineering and Infrastructures (MEIL), which is the second-biggest buyer of electoral bonds — at ₹966 crore — and is facing investigation, has put its city gas distribution business on the block, according to four industry executives aware of the development.

Megha City Gas Distribution (MCGDPL), a wholly-owned subsidiary, has decided to consolidate operations and reached out to state-run Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp and Indraprastha Gas, among other players.

“The companies are evaluating the proposal and study-

ing numbers. No decision has been taken yet,” said an executive in the know. A senior industry executive whose company evaluated Megha City Gas’ assets said it had not done much work on the ground. He pegged valuation at ₹1,000-2,000 crore.

MEIL didn’t respond to queries. Neither did IOCL, BPCL, HPCL and IGL.

MEIL is a \$5-billion infrastructure company with a footprint across hydrocarbons, electric buses, defence, power, transport and manufacturing. It ventured into city gas distribution under the brand name Megha Gas in 2015 and continued to operate as MEIL till FY22.

In September 2022, MEIL transferred the business to MCGDPL, which hold licences to set up city gas distribution networks in 62 districts of 10 states.

“Buoyed by the prospects of CGD, many companies had submitted aggressive bids,” said a senior executive at an energy company that evaluated the Megha City Gas proposal. “MCGDPL was one of them. But now they are finding it very capital-intensive to meet their minimum work programme.”

## On the Block

MEIL set up city gas distribution under Megha Gas in 2015

It won CAs in **62 districts of 10 cities** in three auction rounds

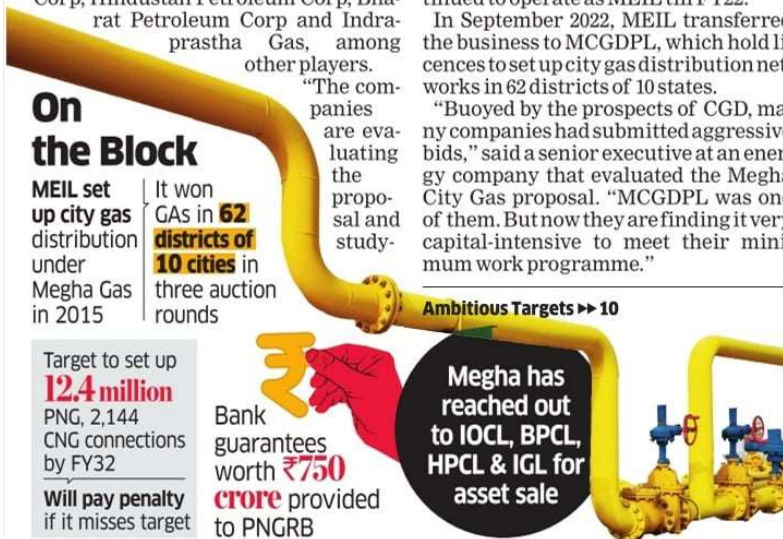
Ambitious Targets ►► 10

Target to set up **12.4 million** PNG, 2,144 CNG connections by FY32

Will pay penalty if it misses target

Bank guarantees worth **₹750 crore** provided to PNGRB

Megha has reached out to IOCL, BPCL, HPCL & IGL for asset sale



# Ambitious Targets

## ►► From Page 1

Thus, (they are) planning to sell the business," said the executive.

The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) auctions geographical areas (GAs) in various rounds for companies to transport or distribute natural gas to domestic, commercial, industrial and transport consumers through a network of pipelines.

According to the rules, city gas distribution companies are required to complete the minimum work programme in their GAs by the end of a designated period.

Megha City Gas had 98,920 domestic piped natural gas (PNG) connections and 146 compressed natural gas (CNG) stations, with a pipeline network of 9,514 km, by end of December 2023.

It needs to implement a cumulative work programme of 12.4 million domestic PNG connections, 2,144 CNG stations and 54,926 inch-km of pipelines across 22 GAs by FY32. A penalty will be applicable if the company misses its targets.

In a February 2024 note, India Ratings and Research (Ind-Ra) said any penalties would impact Ebitda and remain a key monitorable for cash flows and leverage at Megha City Gas.

It provided bank guarantees worth Rs 750 crore to the PNGRB upon winning the GAs. "In the seven GAs won under the fifth and ninth rounds, the company is falling behind its minimum work programme targets... However, so far, no encashment of bank guarantees has happened for any of the GAs won under the fifth and ninth rounds," Ind-Ra said.

According to the rating agency, MCGDPL intends to incur a cumula-

tive capex of Rs 6,400 crore till FY30 to meet the minimum work programme targets for the 11th city gas distribution round. "Of this, MEIL is likely to infuse Rs 4,600 crore as equity/subordinated loans in MCGDPL, with Rs 1,300 crore being funded through debt, and the balance Rs 900 crore being generated through internal accruals of MCGDPL," it said.

In the first nine months of FY24, MCGDPL incurred a capex of Rs 5,500 crore with the support of its parent MEIL, Ind-Ra added.

## GRAFT ALLEGATIONS

"We studied Megha Gas' proposal. If we acquire it, we take on the penalties as well," said an executive of an oil and gas company who did not wish to be identified. "But in light of their recent run-ins with the CBI, we have decided not to evaluate it further."

MEIL had emerged as the second-biggest buyer of electoral bonds and donated the highest amount of about Rs 966 crore to political parties, according to data released by the Election Commission on March 21.

The Supreme Court struck down electoral bonds as unconstitutional in February.

Last month, CBI also registered a case of alleged corruption against MEIL, eight officials of NMDC and NMDC Iron and Steel Plant (NISP), and two officials of Mecon, in connection with a work contract worth over Rs 314.57 crore.

The executive director of an oil and gas company said many companies were unable to achieve targets despite bold bids. "So, they are putting their licences and geographical areas on the block. This is leading to consolidation in the city gas sector. We are anticipating more such consolidation," he said.

# सरकारी उपक्रमों को ज्यादा स्वायत्तता देने के लिए बदलेंगे नियम

हर्ष कुमार  
नई दिल्ली, 26 मई

वित्त मंत्रालय केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न दर्जे वाली कंपनियों के संचालन के लिए प्रवेश नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रहा है। इस मामले के जानकार दो वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इसका मकसद इस श्रेणी में सार्वजनिक क्षेत्र की ज्यादा कंपनियों को शामिल करना है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया, 'हम इस पर काम कर रहे हैं। यह अगली सरकार के 100 दिन के एजेंडे का हिस्सा हो सकता है। नियमों में ढील देने के बाद अधिक संख्या में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रत्न श्रेणी वाली कंपनियों की जमात में शामिल होने की पात्र होंगी।'

इस बारे में जानकारी के लिए वित्त मंत्रालय को ईमेल भेजा गया मगर खबर लिखे जाने तक जवाब नहीं

आया। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को रत्न दर्जा मिलने से उन्हें कारोबार करने में आजादी होती है। उन्होंने कहा, 'इस श्रेणी की कंपनियों को हरेक कारोबारी निर्णय की मंजूरी के लिए सरकार के पास नहीं जाना पड़ता है।'

ओएनजीसी के पूर्व चेयरमैन आर एस शर्मा ने कहा, 'रत्न का तमगा मिलने से केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा बढ़ जाता है। इसके साथ ही जब इस श्रेणी की कंपनी सूचीबद्ध होती है तो उसका मूल्यांकन अधिक होता है। नियमों में ढील से सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों दोनों को मदद मिलेगी।' उपर्युक्त अधिकारी ने कहा, '30 अप्रैल, 2024 तक देश में 13 महारत्न, 20 नवरत्न, 54 श्रेणी 1 की मिनीरत्न, 11 श्रेणी 2 की मिनीरत्न कंपनियां थीं। वर्तमान में देश में 253 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का परिचालन किया जा रहा है।'

महारत्न कंपनी को देसी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराने की



जरूरत होती है और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के विनियमों के अनुसार न्यूनतम 25 फीसदी सार्वजनिक शेयरधारिता के नियम का पालन करना होता है। ऐसी सार्वजनिक कंपनी का सालाना औसत कारोबार 25,000 करोड़ रुपये से अधिक और सालाना औसत नेटवर्थ 15,000

करोड़ रुपये होना चाहिए। इसके साथ ही पिछले तीन साल के दौरान इन कंपनियों का सालाना कर बाद शुद्ध मुनाफा औसतन 5,000 करोड़ रुपये होना चाहिए और ऐसी कंपनियों की अच्छी खासी वैश्विक मौजूदगी होनी चाहिए। वर्ष 2010 में शुरू की गई महारत्न योजना का मुख्य उद्देश्य मेगा

## ‘रत्न’ का तमगा पाने के बदलेंगे नियम

■ वित्त मंत्रालय महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न दर्जे में प्रवेश के लिए नियमों में संशोधन पर कर रही विचार

■ इस श्रेणी की कंपनियों को पूंजीगत व्यय और कारोबारी फैसलों में मिलती है ज्यादा आजादी

■ देश में 13 महारत्न, 20 नवरत्न, 54 श्रेणी 1 की मिनीरत्न, 11 श्रेणी 2 की मिनीरत्न कंपनियां हैं

‘उत्कृष्ट’ और ‘बहुत अच्छा’ समझौता ज्ञापन रेटिंग हासिल करनी होगी। इन कंपनियों को नेटवर्थ में शुद्ध मुनाफे का अनुपात, कुल उत्पादन/सेवाओं की लागत में कर्मचारियों का खर्च, निवेशित पूंजी पर मूल्यहास, ब्याज और कर पूर्व मुनाफा, प्रति शेयर आय और अंतर-क्षेत्रीय प्रदर्शन जैसे 6 चुनिंदा प्रदर्शन संकेतकों में 60 या उससे अधिक कंपोजिट स्कोर हासिल करना चाहिए।

सरकार ने तुलनात्मक लाभ वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान करने और वैश्विक दिग्गज बनने में सहयोग के लिए 1997 में नवरत्न योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत नवरत्न उपक्रमों के बोर्डों को पूंजीगत खर्च, संयुक्त उपक्रमों में निवेश, विलय/अधिग्रहण और मानव संसाधन प्रबंधन आदि में स्वायत्तता और ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। अक्टूबर 1997 में सरकार ने कुछ अन्य मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद ज्यादा स्वायत्तता दी थी।

केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को अपने परिचालन का विस्तार करने और वैश्विक दिग्गज के रूप में उभरने में सशक्त बनाना था।

सरकार द्वारा नवरत्न दर्जा के लिए जो मानदंड तय किए गए हैं उसके अनुसार मिनीरत्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को पिछले 5 साल में तीन साल तक